सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

“मानक संचालन प्रक्रिया”

सहकारिता में सहकार पर राष्ट्रव्यापी अभियान

STANDARD OPERATING PROCEDURE

NATIONWIDE CAMPAIGN ON “COOPERATION AMONG COOPERATIVES”

भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

मानक संचालन प्रक्रिया

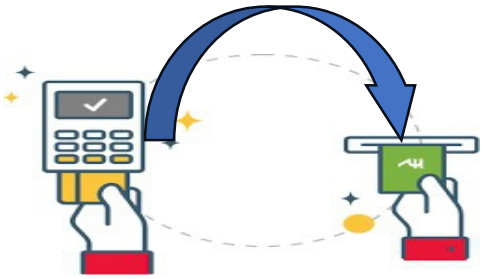

"सहकारिता में सहकार" का राष्ट्रव्यापी अभियान

सितम्बर-2024

(12 जुलाई, 2023 को आयोजित 'सहकारिता में सहकार' अभियान के शुभारंभ के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी महिला डेयरी किसानों को रुपे केसीसी वितरित करते हुए)

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

'सहकारिता में सहकार' का राष्ट्रव्यापी अभियान

1. प्रस्तावना

सहकारी समितियां स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, समता और एकता के मूल्यों पर आधारित हैं।

'सहकारिता में सहकार' सहकारी आंदोलन के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह आंदोलन को सशक्त करने और अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को एक साथ लाकर तालमेल प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को दर्शाता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र 'सहकार से समृद्धि' पहल के तहत 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल में माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सहकारी बैंकों के साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के वित्तीय लेन देन को प्रोत्साहित करना है । पायलट परियोजना की सफलता के उपरांत सहकारी क्षेत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त करने से लेकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) से शीर्ष पहल के तहत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 15 जनवरी, 2024 को गुजरात के सभी जिलों में 'सहकारिता में सहकार' पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था।

2. गुजरात में पायलट जिलों और राज्यव्यापी अभियान के दौरान उपलब्धियां:

गुजरात राज्य के पायलट जिलों बनासकांठा और पंचमहल में 4 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए और 750 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि प्राप्त हुई। नए बैंक मित्र प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) को कुल 1732 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए और किसानों को 20,000 नए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए।

राज्यव्यापी अभियान के दौरान गुजरात में प्रगति निम्नानुसार है:

15.01.2024 से 30.08.2024 के दौरान गुजरात में प्रगति					
नामांकित बैंक मित्र	वितरित mATM	वितरित RuPay KCC	mATM के माध्यम से डिजिटल लेनदेन	खोले गए जमा खाते	कुल प्राप्त जमा राशि
2762	2600	83,941	23.60 लाख	9.40 लाख	रु. 3853 करोड़

(स्त्रोत: नाबॉर्ड पाक्षिक रिपोर्ट)

अभियान की सफलता की कहानी

श्रीमती कंडली हस्तुबेन शामलाभाई, एक डेयरी किसान, बनासकांठा जिले की चांगडा मिल्क सोसायटी को दूध की आपूर्ति करती हैं। बनास डेयरी की सदस्य होने के कारण उन्हें हर 15 दिन अर्थात महीने की 1 और 16 तारीख को अपने दूध की आपूर्ति के एवज में भुगतान उनके बचत बैंक के खाते में मिलता है । चूँकि उन्हें परिवार की दैनिक खपत और पशु चारा खरीदने के लिए यदाकदा पैसे की आवश्यकता होती थी, उस कारणवश उन्हें निकटतम बैंक-शाखा में जाना होता था, जो उनके घर से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चूँकि उनके पति अपनी बाइक से बैंक शाखा जाते हैं, इसलिए पेट्रोल पर पैसे खर्च करने होते थे और इसमें समय की भी हानि होती थी। चांगडा मिल्क सोसाइटी में माइक्रो-एटीएम की तैनाती के बाद वह जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने में सक्षम हो गईं। इससे पैसे और समय दोनों की बचत हुई। कुछ दिनों पूर्व बनास बैंक ने उन्हें 50,000 रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ केसीसी कार्ड भी जारी किया है, अब वह जरूरत पड़ने पर शून्य ब्याज दर पर पैसे निकालने में सक्षम हो गईं और साहूकारों के भारी ब्याजदरों से बच गईं ।

3. अभियान के लक्ष्य

अभियान का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) को केंद्रीय जिला सहकारी बैंक (DCCB)/राज्य स्तरीय सहकारी बैंक (StCB) के माध्यम से **विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच** प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिससे उन लोगों

तक पहुंच बढ़ सके जो सामाजिक-आर्थिक पिरामिड के निम्नतर स्तर में हैं। मोटे तौर पर, उद्देश्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(क) सभी PACS, PDCS को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं हेतु DCCB/StCB से **लिंक** किया जाना।

(ख) PACS, PDCS और अन्य सभी सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को **माइक्रो ATM द्वारा डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं** प्रदान करना।

(ग) PACS, PDCS और अन्य सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को **रुपे KCC** वितरित कर **शून्य अथवा कम ब्याज दर** (इन्टरेस्ट सब्वेन्शन) पर रियायती ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

4. रूपरेखा

हितधारक

इस अभियान से जुड़े हितधारकों में राज्य सरकार (सहकारिता विभाग),सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), केंद्रीय जिला सहकारी बैंक (DCCB) / राज्य स्तरीय सहकारी बैंक (StCB), राज्य दुग्ध महासंघ, जिला दुग्ध संघ और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशों के तहत सभी सहकारी समितियां सम्मिलित होंगी ।

कार्यान्वयन समयसीमा

पायलट परियोजना के गुजरात में कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर राष्ट्रव्यापी **लॉन्च के एक वर्ष के भीतर** पूरे अभियान को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाना है।

(क) राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय कार्यशालाएँ अभियान शुरू होने के **एक महीने के भीतर** पूरी की जानी हैं।

(ख) सदस्यता अभियान, जिसमें खाता खोलने की प्रक्रिया, ***'बैंक मित्रों'*** की नियुक्ति, mATMs जारी करना आदि शामिल है, अभियान शुरू होने के **दो महीने के भीतर** पूरा किया जाना है।

5. प्रक्रिया के चरण

DCCB/StCB कार्यरत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) और अन्य गैर-क्रेडिट सहकारी समितियों को ***'बैंक मित्र'*** के रूप में नियुक्त करेगा।

(क) इन समितियों को एक माइक्रो-एटीएम (mATM), एटीएम का एक लघु संस्करण प्रदान किया जाएगा ताकि वे सामाजिक-आर्थिक पिरामिड के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें।

Micro-ATM एक हैंड हेल्ड, पोर्टेबल और संशोधित पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) टर्मिनल है जिसका उपयोग नकदी निकालने के लिए किया जाता है जो मूलतः (बैंक इन-ए-बॉक्स) की तरह है।

Micro-ATM की विशेषताएं निम्नलिखित हैं,

I. यह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) आधारित लेनदेन दोनों प्रदान करते हैं।
II. ये इंटर ऑपरेबल हैं अर्थात, अन्य बैंकों के ग्राहकों के कार्ड/बायोमेट्रिक्स के उपयोग की अनुमति देते हैं।
III. ये बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा अनुमोदित तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन करते हैं।
IV. डेयरी किसानों के लिए बैंकिंग सेवाओं को किफायती, सुलभ और मूल्यवान बनाने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां इन केंद्रीय जिला सहकारी बैंक (DCCBs) / राज्य स्तरीय सहकारी बैंक (StCB) के दिशा निर्देशन में mATM संचालित करेगा और अपने

संबंधित केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों (DCCBs/StCBs) में समितियों और उसके सदस्यों के बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करेगा ।

(ग) DCCB/StCB इन समितियों के सदस्यों को रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करेंगे और अपने संचालन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

(घ) DCCB/StCB, PACS के सदस्यों को फसल और पशुपालन ऋण के लिए KCC-सीमा जारी करने के माध्यम से ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) सहकारी समितियों के पंजीयक को 'सहकारिता में सहकार' सिद्धांत के अनुरूप DCCB/StCB,राज्य में सभी सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करेगा।

6. अभियान का कार्यान्वयन- भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
	क. अभियान के लिए प्रारंभिक तैयारी	
1.	राज्य सरकार द्वारा सभी हित धारकों को आवश्यक ***अनुदेश/दिशानिर्देश*** मानक संचालन प्रक्रिया जारी करना। (क) राज्य सरकार/राज्य दुग्ध संघों/ जिला दुग्ध यूनियनों द्वारा सभी संबद्ध-प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) और उनके सदस्यों को DCCBs/StCBs में बैंक खाता खोलने के लिए अनुदेश जारी करना। (ख) इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी सहकारी संस्थानों (APMCs सहित) को अपने खाते की सभी शेष राशि DCCBs/StCBs में स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित करना और इन बैंक खातों के माध्यम से अपना व्यवसायिक कार्य शुरू करने के निर्देश जारी करना ।	राज्य सरकार
2.	(क)अभियान शुरू करने और इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रसार के लिए राज्य सहकारी बैंक द्वारा राज्य स्तरीय ***बैठकों/ कार्यशालाओं*** का आयोजन एवं संचालन करना ।	राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) एवं RCS

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
	(ख) इसके अलावा, अभियान के बारे में सभी जिलास्तर के अधिकारियों और विभिन्न सहकारी संस्थानों के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए DCCBs/StCBs द्वारा जिला स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन करना एवं डीसीडीसी (जिला सहकारी विकास समिति) की उप-समिति का गठन।	संबंधित जिला रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (DRCS)
	(ग) इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी बैंकिंग खातों (जमा और अग्रिम) को सहकारिता के अधीन लाने में सहायता हेतु सभी सहकारी संस्थानों के साथ DCCBs/StCBs द्वारा जोनल/तहसील/प्रखंड-स्तरीय बैठकों का आयोजन करना ।	संबंधित DRCS
3.	अभियान की आवश्यकताओं, विज़न और मिशन के प्रसार के लिए DCCBs/StCBs के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) / प्रबंध निदेशक (MDs) और अन्य कार्मिकों द्वारा तालुका/तहसील/ प्रखंड-स्तरीय कार्मिकों/ डेयरी सहकारी समितियों के पर्यवेक्षकों /दुग्ध संघों के साथ बैठकें करना ।	संबंधित DRCS
4.	mATMs जारी करने के लिए DCCBs/StCBs द्वारा उचित PDCS की पहचान करना।	संबंधित दुग्ध संघ, DCCB/ StCB
5.	अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए DCCBs/StCBs द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पांच से सात गांवों का ***क्लस्टर गठन*** किया जाना। बैंकों द्वारा 5-7 गांवों का एक क्लस्टर बनाना होगा तथा उन गांवों की पैक्स और दुग्ध समितियों को क्लस्टर का सदस्य बनाना होगा। बैंक के फील्ड अधिकारियों और डेयरी पर्यवेक्षकों द्वारा क्लस्टर की पैक्स और दुग्ध समितियों के अध्यक्षों और सचिवों की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाएगी। DCCBs/StCBs-शाखाओं के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल गांवों के आकार, PACS, PDCS, कृषि उपज विपणन समिति (APMCs) और अन्य सभी सहकारी समितियों की संख्या पर क्लस्टरों की संरचना निर्भर करेगी।	संबंधित DRCS, दुग्ध संघ, DCCB/StCB

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
6.	दुग्ध यूनियनों के समन्वय से DCCBs/StCBs: (क) PDCS के सभी सदस्य जो वर्तमान में किसी भी PACS के सदस्य नहीं हैं, को PACS में ऑनबोर्ड करेंगे। (ख) इसी तरह, PACS के ऐसे सदस्य जो वर्तमान में किसी भी PDCS के सदस्य नहीं हैं, और जो डेयरी कृषि में लगे हुए हैं लेकिन निजी खरीददारों या अन्य खुदरा विक्रेताओं को दूध बेचते हैं, को PDCS के दायरे में लाना ।	संबंधित DRCS
7.	PACS और PDCS, दोनों और उनके सदस्यों की सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए DCCBs/StCBs उन्हें सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ।	सहकारिता विभाग एवं RCS
8.	**नाबार्ड** ने DCCBs/StCBs के परामर्श से निम्नलिखित के लिए **लक्ष्य निर्धारित** किया है: (क) DCCBs/StCBs में समितियों के बैंक खाते खोलना एवं DCCBs/StCBs द्वारा रुपे KCC जारी करना (ख) DCCBs/StCBs में PDCS के सदस्यों के बैंक खाते खोलना, और (ग) DCCBs/StCBs द्वारा जमाराशि एकत्र करना ।	नाबार्ड एवं DCCBs / StCBs
	ख. अभियान का कार्यान्वयन और निगरानी	
1.	DCCBs/StCBs द्वारा यदि पहले से नहीं किया गया है तो, मिशन-मोड में PDCS और अन्य सभी सहकारी समितियों के लिए निम्नानुसार **सदस्यता अभियान** शुरू करना: (क) DCCBs/StCBs में सभी किसानों और सहकारी समितियों के ***बैंक खाते खोलने*** *के लिए प्रोत्साहित करना*। तदनुसार, सहकारी समितियों के सचिवों को खाता खोलने के फॉर्म जमा करने, के वाई सी दस्तावेजों के एकत्रण, आदि के लिए लगाया जाना	संबंधित DRCS

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
	(ख) DCCBs/StCBs में सहकारी संस्थानों के सभी कर्मचारियों के वेतन खाते, FDs/RDs *खोलने के लिए प्रोत्साहित करना*, और (ग) PDCS से जुड़े सभी सदस्यों और अन्य सहकारी समितियों से जुड़े सभी किसानों को ***रुपे डेबिट कार्ड और रुपे KCC जारी करना*** ।	
2.	दुग्ध संघों से संबद्ध अच्छा काम करने वाले PDCS और अन्य सहकारी समितियों को DCCBs/StCBs द्वारा 'बैंकमित्र' के रूप में ***नियुक्त करना*** ।	संबंधित DRCS एवं नाबार्ड के अधिकारी
3.	DCCBs/StCBs द्वारा cash-vans की तैनाती के माध्यम से 'बैंक मित्रों' के लिए नकदी ***उपलब्धता*** और तरलता सुनिश्चित करना ।	DCCB/StCB एवं'नाबार्ड
4.	अभियान में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए PDCS हेतु mATMs के माध्यम से किए गए लेनदेन पर ***'बैंक मित्रों'*** के कमीशन की संरचना तय करने के लिए DCCBs/StCBs द्वारा नीति तैयार करना ।	DCCB/StCB एवं'नाबार्ड
5.	mATMs और डिजिटल लेनदेन के लाभ के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए DCCBs/StCBs एवं दुग्ध संघ द्वारा ग्राम-स्तरीय ***वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों*** का आयोजन करना ।	संबंधित DRCS एवं नाबार्ड के अधिकारी
6.	PDCS में mATMs जारी करने और उन्हें सक्रिय करने की सुविधा के लिए DCCBs/StCBs द्वारा एक समर्पित टीम का गठन करना । इस संबंध में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को श्रमबल सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना ।	RCS एवं StCB
7.	नए बैंक खाते खोलने, आहरण, जमा,आदि से संबंधित कार्यों के लिए बैंक मित्रों को mATMs के उपयोग पर DCCBs/StCBs द्वारा ***प्रशिक्षण*** प्रदान करना ।	DCCB/StCB

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
	इसके अलावा जमा उत्पादों, ऋण उत्पादों और बैंक की ऋण नीति के अनुसार प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों की समझ के लिए सहकारी समितियों को DCCBs/StCBs द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना।	
8.	निर्बाध बैंकिंग लेन देन की सुविधा के लिए DCCBs/StCBs द्वारा ***नकद ऋण*** *(CC)* सीमा की नीति तैयार करना और 'बैंक मित्रों' को समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करना।	DCCB/StCB
9.	DCCBs/StCBs द्वारा अपनी शाखाओं, दुग्ध समितियों के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं और व्यवहार्यता के आधार पर गांवों में भी ***ए.टी.एम इन्सटाल*** करने पर विचार करना ।	DCCB/StCB
10.	मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार DCCBs/StCBs द्वारा सहकारी समितियों के सभी पात्र सदस्यों के बीच KCC-फसल औरKCC- पशुपालन (AH) की संतृप्ति सुनिश्चित करना।	DCCB/StCB
11.	DCCBs/StCBs में अपनी जमाराशि रखने के लिए प्रेरित करने हेतु DCCBs/StCBs द्वारा संभावित सहकारी संस्थानों और APMCs के साथ ***'ग्राहक गोष्ठी'*** आयोजित करना ।	DRCS एवं DCCB/StCB
12.	DCCBs/StCBs द्वारा बैंकों और दुग्ध संघों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों/ कार्मिकों, PACS, PDCS, APMCs और अन्य सभी सहकारी समितियों के अध्यक्षों और सचिवों को शामिल कर क्लस्टर स्तर पर***साप्ताहिक समीक्षा बैठकें*** आयोजित करना ।	संबंधित DRCS एवं नाबार्ड के अधिकारी
13.	**रिपोर्टिंग तंत्र:** (क)अभियान के तहत जिला और राज्य स्तर की प्रगति पर DCCBs/StCBs द्वारा MIS का समेकन और RCS तथा नाबार्ड को प्रेषण । (ख)नाबार्ड द्वारा सभी राज्यों से संबंधित आंकड़ों का समेकन और पाक्षिक आधार पर सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को उनका प्रेषण ।	RCS / नाबार्ड

#	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी
	(ग) परियोजना की प्रगति पर नज़र रखने के लिए रियल टाइम के आधार पर एक डिजिटल डैश बोर्ड का विकास। यह परियोजना की सभी उपलब्धियां, समितियों, सदस्यों, बैंक मित्र, micro-ATMs, फाइनेंसियल लिटरेसी सेंटर (FLCs) का डाटा / सूचना; जमाराशि (संख्या और राशि), KCC ऋण (संख्या और राशि), आदि कैप्चर करेगा ।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नाबार्ड
	ग. अभियान के तहत शामिल अन्य कार्यकलाप	
1.	बैंकिंग क्षेत्र में अपने अग्रणियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहकारी समितियों की स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर DCCBs/StCBs द्वारा ***कस्टमाइज्ड़ ऋण उत्पाद*** डिजाइन करना ।	DCCB/StCB
2.	DCCBs/StCBs के खाता धारक जिला दुग्ध संघ के सभी आपूर्तीकर्ताओं, परियोजना ठेकेदारों, आदि को ***भुगतान के लिए*** राज्य दुग्ध महासंघों द्वारा ***नीति*** तैयार करना	राज्य दुग्ध महासंघ/ जिला दुग्ध संघ
3.	DCCBs/StCBs द्वारा उन स्थानों पर ***एक्स्टेंशन काउंटर खोलना*** जहां APMCs मौजूद तौ हैं लेकिन DCCBs/StCBs की कोई शाखा मौजूद नहीं है जिससे APMCs का खाता DCCBs/StCBs को हस्तांतरित किया जा सके ।	DCCB/StCB एवं नाबार्ड
4.	DCCBs/StCBs द्वारा अपने यहां खाता रखने वाले प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के बीच KCC ऋणों और रुपे KCC की ***संतृप्ति*** के लिए प्रयास करना।	RCS एवं DCCB/StCB

7. 'सहकारिता में सहकार' अभियान का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन- कार्यकलाप समयसीमा के साथ

क्रम सं.	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी	समयसीमा
	अभियान की कुल अवधि		**T+365 दिन**
T	***शुभारंभ का दिन, अर्थात राज्यस्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन के दिन***		
1.	लक्ष्यनिर्धारण और DCDC की प-समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाए	सभी हितधारक	T+15 दिन
2.	प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की पहचान	दुग्ध यूनियन	T+15 दिन
3.	खाता खोलने सहित DCCB/ StCB से PDCS की संबद्धता	StCB/DCCB और नाबार्ड	T+45 दिन
4.	सदस्यता अभियान (खाता खोलने सहित)	StCB/DCCB और PDCS	अनवरत कार्रवाई
5.	अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु PDCS के लिए mATMs के माध्यम से लेनदेन की सुविधा में "बैंक मित्रों" की कमीशन संरचना निर्धारित करने के लिए DCCBs/StCBs द्वारा नीति निर्माण	DCCB/StCB और नाबार्ड	T+15 दिन
6.	**बैंक मित्रों की नियुक्ति** –दुग्ध यूनियनों के साथ सम्बद्ध और अच्छा काम करने वाले PDCS तथा अन्य सहकारी समितियों को DCCBs/StCBs द्वारा "बैंक मित्र" के रूप में नियुक्ति	संबंधित DRCS और नाबार्ड के अधिकारी	T+60 दिन
7.	माइक्रो -ATMs की खरीद और जारी करना	StCB/DCCB औरनाबार्ड	T+60 दिन
8.	कैश – वैन की तैनाती के माध्यम से "बैंक मित्रों" के लिए DCCBs/StCBs द्वारा नकद और लिक्विडिटी की उपलब्धता सुनिश्चित करना	DCCB/ StCB औरनाबार्ड	बैंक मित्रों की नियुक्ति के तुरंत पश्चात
9.	DCCBs/StCBs, के परामर्श से NABARD द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण और प्रगति का पता लगाना: -		
	i) *DCCBs/StCBs द्वारा RuPay KCC जारी करना*	StCB/DCCB औरनाबार्ड	T+60 दिन तक लक्ष्यों का निर्धारण

क्रम सं.	चरण	कार्यवाही करने वाले संस्था/ अधिकारी	समयसीमा
	ii) DCCBs/StCBs द्वारा जमा राशि मोबलाइज़ करना	StCB/DCCB, नाबार्ड औरPDCS	T+60 दिन तक लक्ष्यों का निर्धारण
10.	mATMs और डिजिटल लेनदेन के फ़ायदों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए DCCBs/StCBs और दुग्ध यूनियनों द्वारा ग्राम स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन	DCCB/ StCB, दुग्ध यूनियन और नाबार्ड	T+60 दिनों में पूरा किया जाएगा
11.	बैंकों और दुग्ध यूनियनों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों, PACS, PDCS, APMCs के अध्यक्षों एवं सचिवों, और सभी सहकारी समितियों को शामिल करके क्लस्टर स्तर पर DCCBs/StCBs द्वारा पाक्षिक समीक्षा बैठकों का संचालन	संबंधित DRCS अधिकारी और नाबार्ड	पाक्षिक अंतराल पर समीक्षा
12.	रिपोर्टिंग प्रणाली: *अभियान के अधीन जिला और राज्य स्तरों के प्रगति की MIS डाटा का DCCBs/StCBs द्वारा समेकित करना और RCS एवं* नाबार्ड *को प्रस्तुत करना*	RCS / नाबार्ड	पाक्षिक अंतराल पर MIS
13.	ऐसे स्थानों में जहां APMCs तो हैं पर DCCBs/StCBs की कोई शाखा मौजूद नहीं हैं, में एक्स्टेन्शन काउन्टर खोलना ताकि APMC के खातों का हस्तांतरण DCCB/StCB में किया जा सके ।	DCCB/ StCB और नाबार्ड	T+90 दिन
14.	परियोजना की प्रगति पर नज़र रखने के लिए रियल टाइम के आधार पर एक डिजिटल डैश बोर्ड का विकास। यह परियोजना की सभी उपलब्धियों, समितियों, सदस्यों, बैंकमित्र, micro-ATMs, फाइनेंसियल लिटरेसी सेंटर (FLCs) *का* डेटा/सूचना; जमाराशि (संख्या और राशि), KCC ऋण (संख्या और राशि), आदि।	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नाबार्ड	अक्टूबर 2024 के अंत तक

8.वर्कफ़्लो– सहकारिता में सहकार पर राष्ट्रव्यापी अभियान

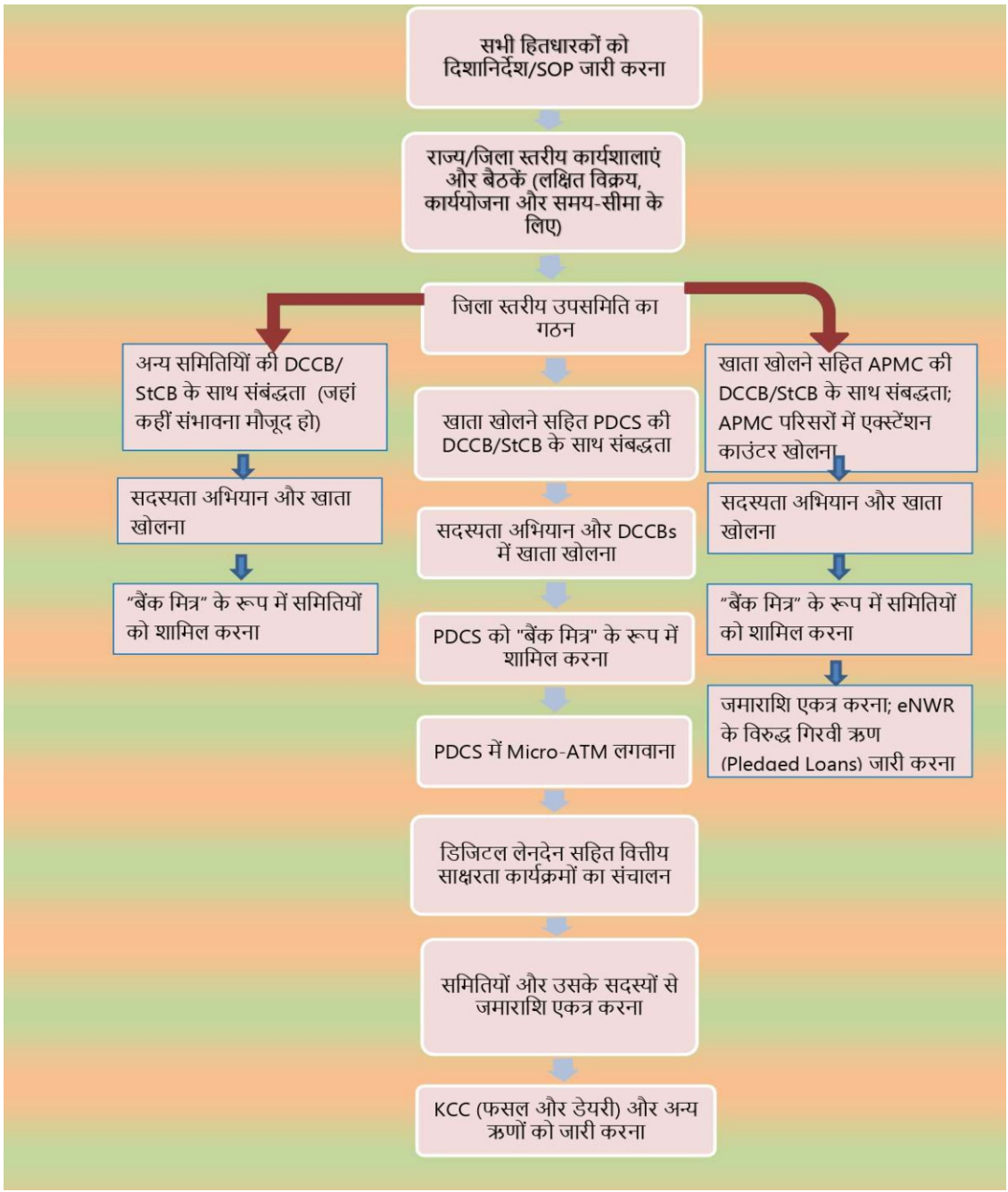

9. दिनांक 12 जुलाई, 2023 और 6 जुलाई, 2024 को आयोजित कार्यक्रमों से संबंधित कुछ तस्वीरें

(गुजरात में 6 जुलाई 2024 को आयोजित 'सहकारिता में सहकार' अभियान के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा महिला डेयरी किसान को रुपे-केसीसी का वितरण)

(12 जुलाई, 2023 को आयोजित 'सहकारिता में सहकार' अभियान के शुभारंभ के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी महिला डेयरी किसानों से मिलते हुए)

(6 जुलाई 2024 को बनासकांठा जिले में महिला डेयरी किसान द्वारा माइक्रो एटीएम पर रुपे केसीसी का उपयोग करते हुए डिजिटल लेनदेन)

(6 जुलाई, 2024 को गुजरात में आयोजित 'सहकार से समृद्धि' सम्मेलन के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एक महिला किसान को प्रोत्साहित करते हुए)

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COOPERATION

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR

NATIONWIDE CAMPAIGN ON "COOPERATION AMONG COOPERATIVES"

SEPTEMBER-2024

(Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji distributing RuPay KCC to women dairy farmers during the launch of 'Cooperation among Cooperatives' campaign held on 12th July, 2023)

Standard Operating Procedure (SOP) for

Nationwide Campaign on 'Cooperation among Cooperatives'

1. Introduction

Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity.

'Cooperation among Cooperatives' is one of the fundamental principles of the cooperative movement. It helps in achieving synergies by bringing together different types of cooperative institutions to strengthen the movement and in increasing their share in the economy. It demonstrates the power of collective action in creating a more equitable and sustainable world.

A pilot project to promote 'Cooperation among Cooperatives' was launched by the Hon'ble Union Minister of Cooperation on 21st May, 2023 in Banaskantha and Panchmahal of Gujarat under the ***'Sahkar Se Samriddhi'*** initiative, the Mantra given by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. The project aimed at promoting financial transactions of primary dairy cooperative societies with cooperative banks. After the success of the pilot project, a statewide campaign on 'Cooperation among Cooperatives' was launched in all districts of Gujarat on 15 January, 2024 to strengthen the cooperative sector from the grassroots, to augment its self-reliance under Primary Agriculture Credit Society (PACS) to Apex initiative.

2. Achievements in the Pilot Districts and during Statewide campaign in Gujarat:

In the Pilot Districts Banaskantha and Panchmahal of Gujarat State, total of more than 4 lakh deposit accounts were opened and deposits of more than Rs 750 crore were received. A total of 1,732 Micro ATMs were distributed to new Bank Mitra primary dairy cooperative societies (PDCS) and 20,000 new RuPay Kisan Credit Card (KCCs) were issued to farmers.

The progress in Gujarat during the statewide campaign is as under:

Progress in Gujarat during 15.01.2024 to 30.08.2024					
Enrolled new Bank Mitras	Distributed micro-ATMs	Distributed RuPay KCC	No. of digital transactions through micro-ATM	No. of deposit accounts opened	Total deposits received
2762	2600	83,941	23.60 lakh	9.40 lakh	₹ 3853crore

(Source: NABARD fortnightly Report)

A success Story of the Campaign

Mrs. Kandli Hastuben Shamlabhai, a dairy farmer from Banaskantha district, supplies milk to the Changda Milk Society. As a member of Banas Dairy, she receives payment for her milk supply credited directly to her Savings bank account every 15 days, on the 1st and 16th of each month. However, she often needed money for daily household expenses and purchasing animal feed. This required frequent visits to the nearest bank branch, which is about 8-10 kilometers away from her home. Her husband would ride his bike to the bank, which resulted in spending money on petrol and losing valuable time.

After the deployment of a micro-ATM at the Changda Milk Society, Mrs. Shamlabhai could withdraw money whenever needed, saving both time and money. Additionally, Banas Bank issued her a Kisan Credit Card (KCC) with a credit limit of Rs. 50,000. This allowed her to access funds at zero interest, freeing her from the clutches of money lenders and ensuring her financial independence.

3. Objective of the Campaign

The objective of the campaign is to enable primary agricultural credit societies (PACS), and PDCS to get **access to various banking services** through District Central Cooperative Banks (DCCBs) / State level Cooperative Banks (StCBs), thereby increasing the outreach to the people who are at the bottom of the socio-economic pyramid. Broadly, objectives may be categorised as under:-

a) To **link** all PACS, PDCS with the District Central Cooperative Bank (DCCB) / State level Cooperative Bank (StCB) for different banking services.

b) To provide **door step banking services** to all members of PACS, PDCS and all other cooperative societies through **micro-ATM.**

c) To distribute **RuPay KCC** to all members of PACS, PDCS and all other cooperative societies to provide concessional loan facility to them at **zero or low interest rate** (interest subvention).

4. Framework

Stakeholders

Stakeholders to be associated with the campaign include State Government (Cooperation Department), Registrar of Cooperative Societies (RCS), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), DCCBs/StCBs, state milk federations, district milk unions, and all cooperative societies, under the overall direction of the Ministry of Cooperation, Government of India.

Implementation Timeline

Based on the experience of implementation of pilot project in Gujarat, the following timeline is to be followed for completion of entire campaign **within a year of Nationwide launch**.

a) State-level and district-level workshops to be completed within a month of launch of campaign.

b) Membership drives, including account opening processes, engagement of ***Bank Mitra,*** issuance of mATMs, etc., to be completed within two months of launch of campaign.

5. Process Flow

DCCBs/StCBs to appoint functional PDCS and other non-credit cooperative societies, as '***Bank Mitra***'**.**

a) A Micro-ATM, a mini version of an ATM, is to be provided to these societies to enable them to provide banking services to the people who are at the bottom of the socio-economic pyramid.

A micro-ATM is a handheld, portable, and modified Point-of-Sale (POS) terminal used to dispense cash. Essentially, it is a 'Bank in a Box'.

Features of micro-ATMs are as under,

i. They provide both OTP (One Time Password) based as well as Aadhaar enabled Payment System (AePS) based transactions.
ii. They are interoperable, i.e., allowing the use of cards/biometrics of customers of other banks.
iii. They comply with technical specifications approved by the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT), the National Payments Corporation of India (NPCI) and the Unique Identification Authority of India (UIDAI).
iv. Can be leveraged to make banking services affordable, accessible and valuable to dairy farmers.

b) PDCS to operate micro-ATMs under the guidance of respective DCCB/StCB and ensure opening of bank accounts of societies and its members in these DCCB/StCB.

c) The DCCB/StCB will issue RuPay debit cards and RuPay Kisan Credit Cards (KCC) to the members of these societies and provide banking services to the cooperative societies functioning in their areas of operation.

d) The DCCBs/ StCBs to ensure credit availability through issuance of KCC-limits for crop and animal husbandry loans to the members of their PACS.

e) The Registrar of Cooperative Societies (RCS) to ensure opening of bank accounts of all cooperative societies in the state and its members, in DCCB /StCB, in line with the 'Cooperation among Cooperatives' principle.

6. Implementation of campaign - Roles and responsibilities

#	Stage	Action to be taken by Institution/ Officers
A. Preparatory steps for the campaign		
1.	Issuance of necessary ***instructions/guidelines****/Standard Operating Procedures (SOPs)* to all stakeholders by the State Government: a) Issuance of instructions by State Governments /State Milk Federations/District Milk Unions, to all affiliated-PDCS and their members, to ensure opening bank accounts with DCCBs/StCBs. b) Further, instructions to be issued by State Government to all cooperative institutions of the state, including Agriculture Produce Marketing Committees (APMCs) to encourage transferring of all of their account balances to DCCBs/StCBs and start their business operations through these bank accounts.	State Government
2.	a) State-level ***meetings/workshops*** to be organised and convened by the StCB, to kick-start the campaign and disseminate its objectives and principles.	State Government (Cooperation Department) & RCS
	b) Further, District-level meetings/workshops to be convened and conducted by DCCBs/StCBs, to sensitize all district-level officials and functionaries of various cooperative institutions, regarding the campaign and formation of sub-committee of DCDC (District Cooperative Development Committee).	Concerned District Registrar of Cooperative Societies (DRCS)

#	Stage	Action to be taken by Institution/ Officers
	c) Additionally, Zonal/ Tehsil/ Block-level meetings to be conducted by DCCBs/StCBs with all cooperative institutions to encourage bringing of all such banking accounts (deposits and advances) within the cooperative fold.	Concerned DRCS
3.	Meetings by Chief Executive Officers (CEOs)/Managing Directors (MDs) and other officials of DCCBs/StCBs with Taluka/Tehsil/Block-level functionaries/supervisors of dairy cooperatives/ milk unions to disseminate the requirements, vision and mission of the campaign.	Concerned DRCS
4.	District Milk Union to identify viable PDCS for issuance of mATMs.	Concerned District Milk Union/DCCB/ StCB
5.	**Cluster formation** of five to seven villages at field-level to be done by DCCBs/StCBs for effective implementation and monitoring of campaign. Banks to make one cluster of 5-7 villages and PACS & Milk Societies of those villages to be made members of the cluster. Weekly meeting of Chairman and Secretaries of PACS & Milk Societies of the cluster to be conducted by Bank field Officers and Dairy Supervisors. The structure of clusters will depend upon the size of total villages covered, number of PACS, PDCS, APMCs and all other cooperative societies, falling within the area of operation of concerned branch of DCCBs/StCBs.	Concerned DRCS, Milk Union and DCCB/ StCB
6.	DCCBs/StCBs, in coordination with milk unions: a) To onboard onto PACS, all members of PDCS, who are currently not members of any PACS. b) Likewise, all members of PACS who are currently not members of any PDCS, and who are engaged in dairy farming but selling milk to private players, or other retailers, to be brought into the fold of PDCS.	Concerned DRCS
7.	DCCBs/StCBs to make arrangements to fulfil all the banking needs of both, PACS and PDCS, and their members, by providing all types of banking services.	Cooperation Department and RCS

#	Stage	Action to be taken by Institution/ Officers
8.	**NABARD,** in consultation with DCCBs/StCBs, to **fix targets** for: - a) Opening of bank accounts of societies with DCCBs/StCBs and issuance of RuPay KCC by DCCBs/StCBs, b) Opening bank accounts of PDCS members with DCCBs/StCBs, and c) Deposit mobilization by DCCBs/StCBs.	NABARD, and DCCBs/StCBs
B. Implementation and monitoring of the campaign		
1.	Initiation of ***membership drive*** in mission-mode, by DCCBs/StCBs for PDCS, and all other cooperative societies, if not already done, by- a) encouraging to ***open bank accounts*** of all farmers and cooperative societies with DCCBs/StCBs. Accordingly, office of secretaries of cooperative societies to be engaged for account opening form submission, collection of KYC documents, etc., b) encouraging opening of salary accounts, Fix Deposits (FDs)/ Recurring Deposits (RDs) of all employees of cooperative institutions with DCCBs/StCBs, and c) ***Issuance of RuPay debit cards and RuPay KCC*** to all the members associated with PDCS, and all farmers associated with other cooperative societies.	Concerned DRCS
2.	DCCBs/StCBs **to *appoint*** well-functioning PDCS affiliated with milk unions, and other cooperative societies, as '*Bank Mitras*'.	Concerned DRCS and Officer of NABARD
3.	DCCBs/StCBs to ensure *cash* ***availability*** and liquidity for '*Bank Mitras*' through deployment of cash-vans.	DCCB/StCB and NABARD
4.	Formulation of policy by DCCBs/StCBs for fixing of commission structure for '***Bank Mitras***' for transactions made through mATMs for PDCS, to motivate them to participate in the campaign.	DCCB/StCB and NABARD
5.	Village-level ***financial literacy programmes*** to be conducted by DCCBs/StCBs and Milk Union to augment awareness regarding benefits of mATMs and digital transactions.	Concerned DRCS and Officer of NABARD
6.	Constitution of dedicated team by DCCBs/StCBs to facilitate issuance and activation of mATMs in PDCS. In this connection, State Cooperative Bank to extend all necessary support including manpower to DCCBs.	RCS and StCB

#	Stage	Action to be taken by Institution/ Officers
7.	DCCBs/StCBs to provide ***training on*** *use of mATMs* to '*Bank Mitras*', covering opening of new bank accounts, withdrawals, deposits, etc. Further, DCCBs/StCBs to provide training for understanding of deposit products, loan products and documents to be obtained as per loan policy of the bank to cooperative societies.	DCCB/StCB
8.	DCCBs/StCBs to formulate ***policy on cash credit (CC) limit*** and ensure timely sanction of the same to "*Bank Mitras*' for facilitation of seamless banking transactions.	DCCB/StCB
9.	DCCBs/StCBs to consider ***installation of ATMs*** in its branches and at milk societies, and also at villages, based on local requirements and feasibility.	DCCB/StCB
10.	DCCBs/StCBs to ensure saturation of KCC-crop and KCC-Animal Husbandry (AH) among all eligible members of cooperative societies, as per extant guidelines.	DCCB/StCB
11.	DCCBs/StCBs to conduct ***'grahak goshthi"*** with potential cooperative institutions and APMCs to encourage them to park their deposits with DCCBs/StCBs.	DRCS & DCCB/StCB
12.	DCCBs/StCBs to conduct ***weekly review meetings*** at cluster-level involving field-level officials/functionaries of banks and milk unions, chairmen and secretaries of PACS, PDCS, APMCs, and all other cooperative societies.	Concerned DRCS and Officer of NABARD
13.	**Reporting Mechanism**: a) DCCBs/StCBs to compile and submit MIS data on progress at district and state-levels, under the campaign to RCS and NABARD. b) NABARD to compile data in respect of all states and submit the same to the Ministry of Cooperation, Government of India, on fortnightly-basis.	RCS / NABARD
	c) Development of a digital dashboard for tracking the project progress on real time basis. It shall capture all project milestones, data/information about societies, members, Bank Mitra, micro-ATMs, FLCs (Financial Literacy Centres); deposits (No. and amount), KCC loans (No. and amount), etc.	NABARD in consultation with Ministry of Cooperation, GoI

#	Stage	Action to be taken by Institution/ Officers
C. Other activities to be covered under the campaign		
1.	DCCBs/StCBs to design ***customised loan products*** based on local needs and requirements of cooperative societies to compete with their peers in the banking sector.	DCCB/StCB
2.	State milk federations to formulate ***policy for routing payments*** to all the suppliers, project contractors, etc., of the district milk unions having accounts with DCCBs/StCBs.	State milk federation/ District Milk Union
3.	DCCBs/StCBs to ***open extension*** counters in places where APMCs exist but no branch of DCCB/StCB is present, so that the account of APMC may be transferred to DCCB/StCB.	DCCB/StCB and NABARD
4.	DCCBs/StCBs to strive for ***saturation*** of KCC loans and RuPay KCC among PM Kisan beneficiaries having accounts with them.	RCS/DCCB /StCB

7. Implementation of the Nationwide Campaign on Cooperation among Cooperatives- Activities with Timelines

S. No.	Step	Action to be taken by Institution/Officers	Timeline
	Total Campaign Period		**T+365 days**
T	***The launching day i.e., the day of conduct of State level workshops***		
1.	District Level Workshops for target setting and Formation of sub-committee of DCDC (District Cooperative Development Committee)	All the stakeholders	T+15 days
2.	Identification of Primary Dairy Cooperative Societies	Milk Unions	T+15 days
3.	PDCS affiliation to DCCB/ StCB including A/c opening	StCB/DCCB and NABARD	T+45 days
4.	Membership drive (incl A/c opening)	StCB/DCCB & PDCS	Ongoing activity

S. No.	Step	Action to be taken by Institution/Officers	Timeline
5.	Formulation of policy by DCCBs/StCBs for fixing of commission structure for 'bank mitras' for transactions made through mATMs for PDCS, to motivate them to participate in the campaign.	DCCB/ StCB and NABARD	T+15 days
6.	**Engagement of Bank Mitras-** DCCBs/StCBs to appoint well-functioning PDCS affiliated with milk unions, and other cooperative societies, as 'bank mitras'.	Concerned DRCS and Officer of NABARD	T+60 days
7.	Procurement and Issuance of Micro-ATMs	StCB/DCCB & NABARD	T+60 days
8.	DCCBs/StCBs to ensure cash availability and liquidity for 'bank mitras' through deployment of cash-vans.	DCCB/ StCB and NABARD	Soon after engagement of Bank Mitras.
9.	NABARD, in consultation with DCCBs/StCBs, to fix targets and track the progress of: -		
	i) *Issuance of RuPay KCC by DCCBs/StCBs*	StCB/DCCB & NABARD	Fixing targets by T+60 days
	ii) Deposit mobilization by DCCBs/StCBs	StCB/DCCB, NABARD and PDCS	Fixing targets by T+60 days
10.	Village-level financial literacy programmes to be conducted by DCCBs/StCBs and Milk Union to augment awareness regarding benefits of mATMs and digital transactions.	DCCB/ StCB, Milk Unions and NABARD	To be completed in T+60 days.
11.	DCCBs/StCBs to conduct fortnightly review meetings at cluster-level involving field-level officials/functionaries of banks and milk unions, chairmen and secretaries of PACS, PDCS, APMCs, and all other cooperative societies.	Concerned DRCS Officer and NABARD	Review at fortnightly intervals

S. No.	Step	Action to be taken by Institution/Officers	Timeline
12.	Reporting Mechanism: *DCCBs/StCBs to compile and submit MIS data on progress at district and state-levels, under the campaign to RCS and NABARD.*	RCS / NABARD	MIS at fortnightly intervals
13.	DCCBs/StCBs to open extension counters in places where APMCs exist, but no branch of DCCB/StCB is present, so that the account of APMC may be transferred to DCCB/StCB.	DCCB/ StCB and NABARD	T+90 days
14.	Development of a digital dashboard for tracking the project progress on real time basis. It shall capture all project milestones, data/information about societies, members, Bank Mitra, micro-ATMs, FLCs (Financial Literacy Centres); deposits (No. and amount), KCC loans (No. and amount), etc.	NABARD in consultation with MoC, GoI	By end of October 2024

8. Workflow – Nationwide Campaign on Cooperation among Cooperatives

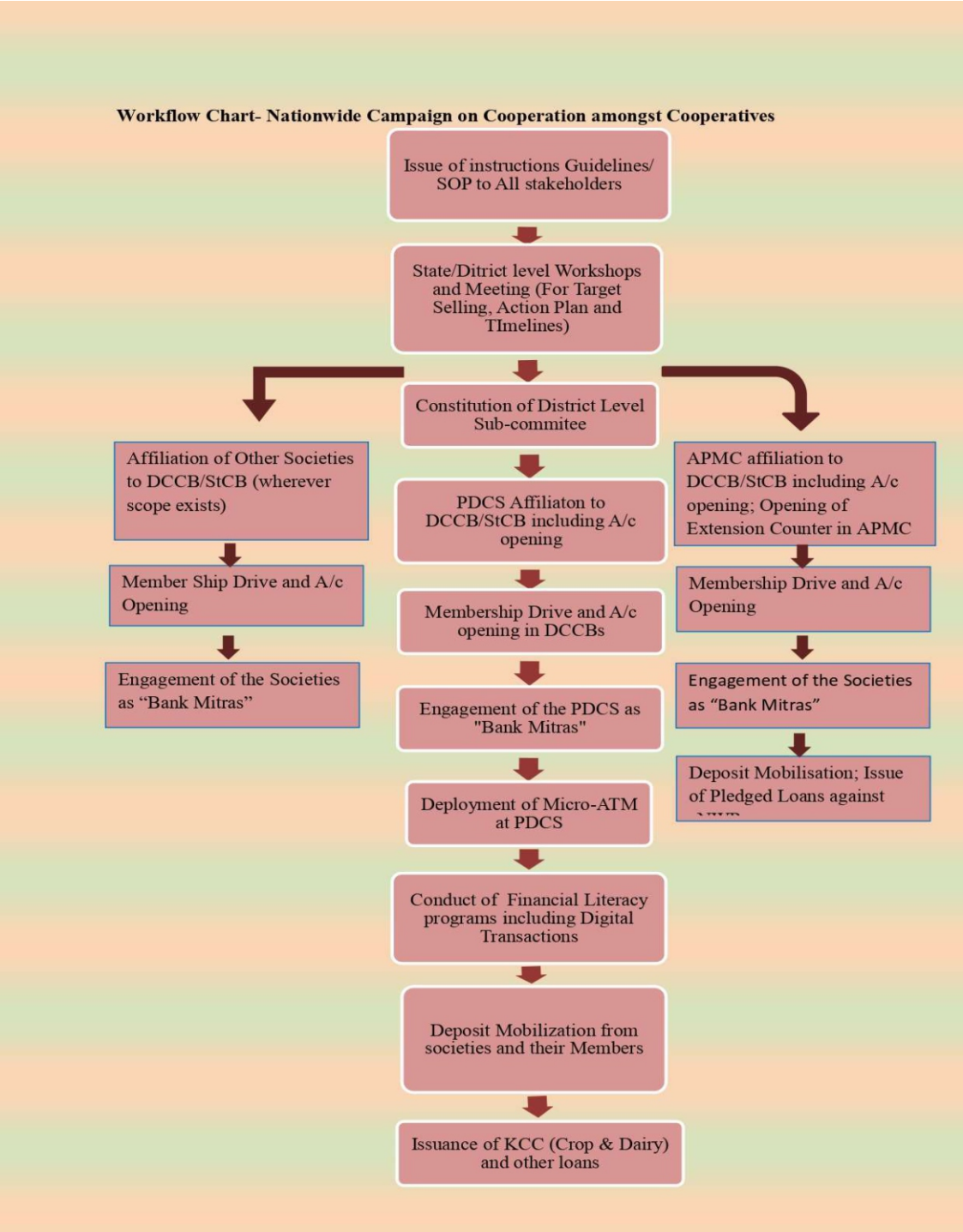

9. Some photographs related to the programmes organized on 12 July 2023 and 06 July 2024

(Distribution of Rupay-KCC to woman dairy farmer by Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji during the 'Cooperation among Cooperatives' campaign held on 6th July 2024 in Gujarat)

(Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji interacting with women dairy farmers during the launch of 'Cooperation among Cooperatives' campaign held on 12th July, 2023)

(Digital transaction using RuPay-KCC on micro-ATM by a woman dairy farmer in Banaskantha district on 6th July 2024)

(Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah ji encouraging a woman farmer during the 'Sahkar se Samriddhi' Conference held on 6th July, 2024 in Gujarat)

****

सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करे –

सहकार से समृद्धि

Website - https://www.cooperation.gov.in/

Twitter Handle - https://x.com/MinOfCooperatn

YouTube Channel - https://www.youtube.com/MinOfCooperatn

Instagram Page - https://www.instagram.com/minofcooperatn

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/minofcooperatn/

Ministry of Cooperation,
Atal Akshya Urja Bhawan
Lodhi Road, New Delhi-110003